पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ति3/9माह वि.व2024 परिणाम
कॉन्फ्रेंस कॉल
फरवरी 08, 2024

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का प्रबंधन:-

- **सुश्री परमिंदर चोपड़ा - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभार**

मोडरेटर: सुश्री श्वेता दफ़्तरदार – एलारा सिक्योरिटीज

मोडरेटर: देवियो और सज्जनो, शुभ दिन और एलारा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ति3 विव2024 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है। एक अनुस्मारक के रूप में, सभी प्रतिभागी पंक्तियाँ केवल-लिसन मोड में होंगी और प्रस्तुति समाप्त होने के बाद आपके लिए प्रश्न पूछने का अवसर होगा। यदि आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने टचटोन फोन पर "*" फिर "0" दबाकर ऑपरेटर को संकेत दें। कृपया ध्यान दें कि यह कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं कॉन्फ्रेंस को एलारा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की सुश्री श्वेता दफ़्तारदार को सौंपता हूं। धन्यवाद और आपका आभार मैडम!

श्वेता दफ़तरदार : धन्यवाद मानव। सभी को शुभ संध्या। एलारा कैपिटल की ओर से, हम वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही और नौ महीने के अर्निंग पर चर्चा करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सम्मानित प्रबंधन टीम में हमारे साथ सुश्री परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त - अतिरिक्त प्रभार है। ज्यादा देर न करते हुए, मैं अब सुश्री चोपड़ा को उनकी प्रारंभिक टिप्पणी के लिए कॉल सौंपती हूं, जिससे पश्चात हम प्रश्नोत्तरी के लिए मंच खोल सकते हैं। धन्यवाद और आपका आभार मैडम।

परमिंदर चोपड़ा: धन्यवाद श्वेता। एक बहुत अच्छी शाम और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पीएफसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर एक अपडेट साझा करके इस कॉल की शुरुआत करना चाहूंगी। जनवरी 2024 में पीएफसी को आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आईएफएससी गिफ्ट सिटी भारत का पहला वित्तीय सेवा केंद्र है। सरकार का लक्ष्य आईएफएससी गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना है जो न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को

सेवाएं प्रदान करेगा। आईएफएससी कई नियामक लाभ प्रदान करता है जैसे लगातार 10 वर्षों तक आय पर 100% कर छूट, सेवा पर कोई जीएसटी नहीं, विदहोल्डिंग टैक्स पर लाभ और कई अन्य। पीएफसी में हमें इस दृष्टिकोण का हिस्सा होने पर गर्व है। मैं बताना चाहूंगा कि पीएफसी आईएफएससी में प्रवेश करने वाली पहली सरकारी एनबीएफसी होगी। पीएफसी की आईएफएससी सहायक कंपनी अंतरराष्ट्रीय ऋण क्षेत्र में हमारे लिए रास्ते खोलेगी और पीएफसी के ब्रांड को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद करेगी।

अब मैं वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए पीएफसी के वित्तीय और परिचालन कार्य-निष्पादन पर चर्चा करूंगी। समेकित फ्रंट पर हम लगातार मजबूत कार्य-निष्पादन देख रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष और नौ महीनों के लिए समेकित पीएटी पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि के साथ 18,900 करोड़ रुपये है। तीसरी तिमाही के लिए कर पश्चात लाभ 6294 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 20% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में समूह की ऋण परिसंपत्ति बुक में साल दर साल 19% की वृद्धि दर्ज की गई। 31 दिसंबर, 2023 तक समेकित ऋण परिसंपत्ति बुक 9,54,483 करोड़ रुपये है। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर हमारे केंद्रित समाधान प्रयासों के कारण समेकित निवल एनपीए अनुपात अब 1% से नीचे है और दिसंबर 2022 में 1.15% की तुलना में 0.86% है। अगर हम 2024 के नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन कार्य-निष्पादन के बारे में बात करते हैं, तो पीएफसी के मुनाफे में गिरावट देखी गई। नौ महीने 2023 में 8113 करोड़ रुपये से 26% की वृद्धि के साथ नौ महीने 2024 में 10,232 करोड़ रुपये हो गई। लाभ में वृद्धि मुख्य रूप से बढ़े हुए परिसंपत्ति आधार पर ब्याज आय में वृद्धि, भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव सीमाबद्ध होने और एनपीए परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण स्थिर प्रावधान के कारण है। तिमाही के लिए कर पश्चात लाभ 3377 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। इस तिमाही में भी शेयरधारकों के साथ अपनी सफलता साझा करने के प्रयास को जारी रखते हुए हमारे बोर्ड ने 3.5 रुपये प्रति शेयर का

अंतरिम लाभांश घोषित किया है। इसके साथ वित्त वर्ष 2024 के लिए संचयी अंतरिम लाभांश बढ़े हुए पूंजी आधार पर 8 रुपये प्रति शेयर है।

अब हम अपने प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर आते हैं। यदि हम 2024 के नौ महीनों के लिए यील्ड को देखें, तो यह 10.02% है, जो कि 2024 की पहली छमाही की तुलना में 10 बीपीएस की वृद्धि है। जैसा कि हम अपने पहले संचार में साझा करते रहे हैं, ब्याज दर में वृद्धि का प्रभाव अब हमारी यील्ड पर दिखाई देने लगा है। नौ महीनों के लिए फंड की लागत 7.47% की अपेक्षित सीमा के भीतर है और यदि आपको याद हो, तो हम हमेशा स्प्रेड और एनआईएम के बारे में हमारी निर्देशित सीमा के भीतर होने की बात करते रहे हैं और तदनुसार 2024 के नौ महीनों के लिए हमारा स्प्रेड 2.55% और एनआईएम 3.42% पर है। पूंजी फ्रंट पर हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 दिसंबर, 2023 को 26.86% और टियर वन पूंजी 24.28% है।

अब मैं परिसंपत्ति गुणवत्ता पर हमारी प्रगति पर चर्चा करूंगी। इस तिमाही में हम 413 करोड़ रुपये के डैन्स एनर्जी ऋण के समाधान तक सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं। यह पहले साझा किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप है। समाधान में एनसीएलटी के बाहर मौजूदा ऋण का पुनर्गठन शामिल था। समाधान के बाद परिसंपत्ति चरण तीन यानी एनपीए श्रेणी से बाहर हो गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कोई नई गिरावट नहीं आई है। इसके साथ ही हमारा निवल एनपीए अनुपात 1% से नीचे 0.9% पर है। यह पिछले छह वर्षों में सबसे कम निवल एनपीए है। इसके अलावा हमारा सकल एनपीए भी 2023 के नौ महीनों में 4.21% से 69 आधार अंक की उल्लेखनीय गिरावट के साथ वित्त वर्ष 2024 के नौ महीनों में 3.52% हो गया है। अब डैन्स ऊर्जा समाधान के बाद हमारे पास चरण तीन के तहत लगभग 16,000 करोड़ रुपये की 21 दबावग्रस्त परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में से 2174 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं का समाधान किया जा रहा है। एनसीएलटी के तहत 13,899 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का समाधान किया जा रहा है, जिनमें से 2620 करोड़ रुपये की सात

परियोजनाएं परिसमापन प्रक्रिया के तहत हैं और लगभग 11,200 करोड़ रुपये की छह परियोजनाएं एनसीएलटी में समाधान के विभिन्न चरणों में हैं। 21 परियोजनाओं में से 2376 करोड़ रुपये की लैंको अमरकंटक परियोजना समाधान के उन्नत चरण में है। यह 1920 मेगावाट की तापीय उत्पादन परियोजना है और एनसीएलटी के तहत समाधान पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऋणदाताओं द्वारा समर्थित समाधान योजना एक सफल समाधान योजना के रूप में एनसीएलटी को प्रस्तुत की गई थी। एनसीएलटी में ऋणदाताओं द्वारा समर्थित समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद, कई पक्षों ने परियोजना के लिए बेहतर समाधान योजना प्रस्तुत करने में रुचि व्यक्त की। इस पर एनसीएलटी ने ऋणदाताओं को फिर से स्विस चेलेंज प्रोसेस संचालित करने की अनुमति दे दी है। स्विस चेलेंज प्रोसेस 6 फरवरी, 2024 को की गई है और मूल्यांकन के आधार पर और सीओसी के अनुमोदन के बाद सफल समाधान योजना अनुमोदन के लिए एनसीएलटी को प्रस्तुत की जाएगी। यदि हम प्रावधान के बारे में बात करते हैं, तो हमने चरण तीन परिसंपत्तियों पर 74% प्रावधान कवरेज बनाए रखा है, जो हमारा मानना है कि पर्याप्त है। इस तिमाही में हमने परियोजना की वर्तमान समाधान स्थिति को देखते हुए चरण तीन परिसंपत्तियों पर प्रावधान भी बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप डैन्स ऊर्जा परियोजना के समाधान जैसे सकारात्मक विकास के बावजूद प्रावधानों में समग्र वृद्धि हुई है, जिससे प्रावधान रिवर्सल हो गया है।

अब पीएफसी की ऋण बुक पर आते हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में हमने लगभग 79,000 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। साल-दर-साल आधार पर हमारा संवितरण लगभग 1.7 गुना बढ़ गया है। संवितरण में वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के तहत वितरण क्षेत्र को ऋण देने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ऋण देने से प्रेरित है। संवितरण में बढ़ोतरी से हमारी ऋण परिसंपत्ति बुक में साल-दर-साल 16% की वृद्धि हुई है। 31 दिसंबर, 2023 तक हमारी ऋण परिसंपत्ति बुक 4,57,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024 के लिए, हम वित्त वर्ष 2023 के समान स्तर पर ऋण परिसंपत्ति वृद्धि बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए भविष्य के

ऋण वृद्धि दृष्टिकोण के संबंध में दो क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि ये पूरक होंगे। पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा में पीएफसी के पारंपरिक ऋण व्यवसाय में से एक, इसे प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना द्वारा समर्थित किया जाएगा जो एक जबरदस्त व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना की घोषणा हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2024 को की गई थी। सूर्योदय योजना के तहत, देश भर में 1 करोड़ घरों को सोलर रूफ टॉप मिलेगा। 40 गीगावाट सोलर रूफ टॉप के दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सूर्योदय योजना शुरू की गई है। यह योजना देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। यह योजना राज्य डिस्कॉम और विद्युत मंत्रालय के तहत आठ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित एसपीवी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। हमारी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड को सूर्योदय योजना के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 40 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 60,000 रुपये प्रति किलोवाट की अस्थायी कार्यान्वयन लागत के आधार पर कुल वित्तीय लेआउट लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से औसतन लगभग 50% फंडिंग सरकारी सहायक कंपनी के माध्यम से आने की उम्मीद है। यह आने वाले वर्षों में 1.2 लाख करोड़ रुपये के संभावित वित्तपोषण अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा यह योजना पीएफसी के लिए संपूर्ण सोलर वेल्यू चेन जैसे उपकरण निर्माण आदि में अतिरिक्त ऋण देने के अवसर भी पैदा करेगी। इन फंडिंग अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारे बोर्ड ने आज 1.70 लाख करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। हमारा मानना है कि यह योजना आने वाले वर्ष में हमारी विकास संभावनाओं को बढ़ाएगी। एक और संभावित वित्त पोषण क्षेत्र जो हम देखते हैं वह सरकारी योजना के तहत वितरण क्षेत्र में निरंतर ऋण देने के अवसर हैं। 2022 में, भारत सरकार ने DISCOMs को 3 जून, 2022 तक उनके पुराने बकाया को चुकाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए LPS यानी विलंबित भुगतान अधिभार योजना शुरू की है। यह योजना बड़ी सफल रही है जिसके परिणामस्वरूप विरासती बकाया में 60% से अधिक की कमी आई है। 31 दिसंबर, 2023 तक पीएफसी ने एलपीएस के

तहत संचयी रूप से 33,312 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। साथ ही एलपीएस के तहत अपनाए गए दृष्टिकोण ने बकाया भुगतान न करने पर डिस्कॉम की खुली पहुंच को विनियमित करके डिस्कॉम के बीच राजकोषीय अनुशासन में सुधार किया है। इस संख्या का समर्थन करने के लिए, विव2023 से वर्तमान तक, DISCOM को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की राशि का बिल दिया गया है। इसमें से केवल 10% से कम ही अभी अतिदेय है। इन बकाए का प्रबंधन करने के लिए पीएफसी, डिस्कॉम को एक वर्ष तक की चक्रीय बिल भुगतान सुविधा प्रदान कर रहा है। 31 दिसंबर, 2023 तक पीएफसी ने योजना के तहत संचयी रूप से 51,000 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। हमें उम्मीद है कि अगले साल भी योजना में फंडिंग जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम योजना के तहत पूंजीगत व्यय कार्य कार्यान्वयन की गति के आधार पर संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के आसपास उभरने के अवसर भी देखते हैं। इन आशाजनक मार्गों का लाभ उठाते हुए हम अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकारात्मक ऋण परिसंपत्ति दृष्टिकोण देखते हैं।

ख़त्म करने से पहले मैं दो नियामक घटनाओं को संबोधित करना चाहती हूँ। एक यह है कि पीएफसी ने कल एक्सचेंज पर एलसीआर जुर्माने के बारे में घोषणा की है। आरबीआई ने हाल ही में 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई, एनबीएफसी के तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया है। इस पर मैं सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि यह जुर्माना पीएफसी की समग्र तरलता स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तरलता कवरेज अनुपात को बनाए रखना संभावित तरलता के लिए आसानी से वसूली योग्य तरल संपत्ति रखने का एक साधन है। यह कंपनी की दिन-प्रतिदिन की तरलता स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। पीएफसी तरलता के मोर्चे पर अच्छी स्थिति में है और बिना किसी समस्या के अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है।

अब बात आती है कि यह जुर्माना क्यों लगाया गया है, यह जुर्माना पात्र उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों के संबंध में व्याख्या में अंतर के कारण लगा। पीएफसी ने सावधि

जमा को एचक्यूएलए माना जबकि आरबीआई ने इसे एलसीआर गणना के लिए योग्य एचक्यूएलए नहीं माना। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2022 के लिए एलसीआर में अंतर आ गया जिसके कारण जुर्माना लगाया गया। अब हम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को आरबीआई की व्याख्या के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि इसका हमारे व्यवसाय संचालन या वित्तीय ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीएफसी विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है।

अब 15 जनवरी, 2024 को आरबीआई द्वारा जारी ड्राफ्ट सर्कुलर पर आते हैं। यह सर्कुलर पीएफसी जैसे सरकारी एनबीएफसी को आरबीआई के क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों के दायरे में लाता है। अब निवेशकों के बीच यह चिंता पैदा हो गई है कि इससे हमारी ऋण देने की क्षमता, विशेषकर हमारी सरकारी बहीखाते पर असर पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएफसी वर्षों से सक्रिय रूप से ऋण संकेंद्रण का प्रबंधन कर रहा है। हम 2010 से अपने निजी क्षेत्र की ऋण पुस्तिका पर इन मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं और 2022 में हमने आरबीआई के विशिष्ट निर्देश के अनुरूप उन्हें अपने सरकारी उधारकर्ताओं के लिए अपनाया है। वर्तमान में हमारे पास अपनी सरकारी बुक के लिए भी ऋण देने की पर्याप्त गुंजाइश है। हमारी कुल सरकारी बही में लगभग 12.8 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। हमारे शीर्ष 10 ऋणकर्ताओं के लिए, जो हमारी बकाया बही का लगभग 40% हिस्सा हैं, हमारे पास 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक्सपोजर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों को एक्सपोज़र सीमा से बाहर करने से और भी अधिक लचीलापन मिलता है। इस प्रकार पीएफसी सरकारी ऋण व्यवसाय का समर्थन करने और विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

निष्कर्ष के तौर पर तीसरी तिमाही स्थिर रही है जो लगातार कार्य-निष्पादन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हम इस गति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। कॉल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर शुरू कर सकते हैं।

मोडरेटर: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न सीएलएसए से श्रेय शिवानी की पंक्ति से है। सर कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्रेय शिवानी: अवसर के लिए शुक्रिया। महोदया, मेरे दो प्रश्न हैं और यह अधिकतर ऋण बुक और संवितरण के संबंध में है, विशेष रूप से एलपीएस योजना के संवितरण के संबंध में? सितंबर 2023 तक आपने उल्लेख किया था कि एलपीएस के तहत स्टैंडअलोन बुक के लिए संस्वीकृति 705 अरब रुपये थी, जिसमें से वितरण 315 अरब रुपये था और अभी आपने अपडेट किया है कि दिसंबर तक संवितरण 333 अरब रुपये है, तो क्या कारण था कि इस एलपीएस योजना के तहत इस तिमाही में वितरण कम था और प्रभावी रूप से आधा वितरण आपके द्वारा स्वीकृत राशि से कम है, तो इसका कारण क्या है? क्या मुझे अगली तिमाही के लिए भी DISCOMs के तहत धीमें संवितरण की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम विव2024 के लिए ऋण वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं कि आप विव 2023 ऋण बुक को विव 2024 में दोहराएंगे जो कि 13% ऋण पुस्तिका है जिसका अर्थ है हम ति4 में धीमे हो जाएंगे, मैं वित्त वर्ष 2025 की गतिशीलता को समझना चाहता हूं और महोदया, यह देखते हुए कि हमारे पास अभी भी कई खंडों के साथ विकास चालक हैं, शायद इन्फ्रा सेगमेंट भी है, जिसमें संवितरण अब शुरू हो गया है, क्या हमें वित्त वर्ष 2025 में कोई मार्गदर्शन मिल सकता है क्या यह वित्त वर्ष 2023 या वित्त वर्ष

2024 से काफी बेहतर होगा, जिसका आप संकेत दे रहे हैं कि 13% की वृद्धि होगी, तो मोटे तौर पर मेरे प्रश्न इन्हीं के आसपास हैं?

परमिंदर चोपड़ा : हाँ। शिवानी आपने दो प्रश्न पूछे हैं। मैं एलपीएस योजना के बारे में पहला प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि एलपीएस योजना में बकाया राशि के आधार पर 12 मासिक किस्तों से 48 मासिक किस्तों के बीच किस्तों का विकल्प चुनने का प्रावधान है। इसलिए जहां भी किस्त की राशि कम थी, वहां 100% संवितरण पहले ही किया जा चुका है, इसलिए कुछ मामले ऐसे हैं जहां किस्तों को आगे बढ़ाने का विकल्प 36 या 48 किस्तों के लिए हो सकता है, इसलिए तदनुसार केवल उन मामलों में किश्तें जारी की जा रही हैं अभी भुगतान किया गया है और तदनुसार एलपीएस संवितरण, जब यह परिपक्व हो जाएगा तो इसे आगे बंद कर दिया जाएगा और तदनुसार हमारा संवितरण आगे चलकर चरण दर चरण कम हो सकता है, इसलिए यह एलपीएस पर है। इन्फ्रा सेक्टर पर पीएफसी द्वारा अब तक कुल 31,222 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई है, इसलिए पाइपलाइन में कुछ अन्य प्रमुख संस्वीकृति भी हैं और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि संस्वीकृति और संवितरण के बीच हमेशा कुछ समय लगता है क्योंकि ऋणकर्ता को अनुपालन करना होता है। कुछ पूर्व-प्रतिबद्धता शर्तों के साथ, फिर दस्तावेज़ जो होता है और फिर कुछ पूर्व-वितरण शर्तों की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही बुनियादी ढांचे में संवितरण शुरू होता है, इसलिए अब तक बुनियादी ढांचे में संवितरण लगभग 2726 करोड़ रुपये हो चुका है और हम धीरे-धीरे इसमें चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में वृद्धि देख रहे हैं।

श्रेय शिवानी : महोदया, वित्त वर्ष 2025 के लिए कोई मार्गदर्शन, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे कि एलपीएस योजना वितरण धीमा हो जाएगा, इसलिए वित्त वर्ष 2024 में हमें वित्त वर्ष 2025 में केवल 13% वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए?

परमिंदर चोपड़ा : देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो और योजनाएं हैं, एक सूर्योदय योजना जो सोलर रूफटॉप के लिए घोषित की गई है और आप जानते होंगे कि पीएफसी सक्रिय रूप से उपकरण निर्माण के लिए ऋण भी संस्वीकृत कर रहा है, इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री को बढ़ावा देने के लिए वहां हैं। रूफटॉप सोलर के साथ-साथ मेक इन इंडिया अवधारणा का दृष्टिकोण, इसलिए हमने सौर उपकरण संयंत्र के लिए शीर्ष निर्माताओं या शीर्ष कंपनियों को वित्त पोषित किया है। एक तो यह कि और अन्यथा हम आगे चलकर रूफटॉप सोलर की स्थापना के लिए भी वित्त पोषण के अवसर की तलाश में हैं। दूसरी चीज़ है आरडीएसएस योजना। मैं सहमत हूं कि अब तक आरडीएसएस के तहत प्रगति की गति धीमी रही है, लेकिन अब ज्यादातर मामलों में अनुबंध अवॉर्ड पहले ही किया जा चुका है, घाटे में कमी के तहत 1,28,000 करोड़ रुपये का अवॉर्ड पहले ही दिया जा चुका है और अन्यथा प्रीपेड मीटर का भी ऑर्डर दिया गया है, इसलिए एक बार ऑर्डर देने के बाद, वास्तव में अनुबंध का निष्पादन शुरू हो जाता है, इसलिए अंततः आरडीएसएस के तहत जो भी संवितरण होता है, हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा करना मुझे लगता है कि यह हमें सामान्य उत्पादन से अलग करता है। पारंपरिक उत्पादन, चाहे वह नवीकरणीय उत्पादन हो, ट्रांसमिशन हो या वितरण के तहत पूंजीगत व्यय हो, ये दो योजनाएं हमें अतिरिक्त लाभ देंगी और आरबीपीएस हमने पहले ही कहा था कि यह वर्तमान बकाया के लिए है और हम अल्पावधि में फंडिंग जारी रखेंगे।

श्रेय शिवानी : समझ गया मैडम। बस आखिरी सवाल यह है कि एलपीएस योजना में शेष किस्तों के लिए कितना अधिक वितरण किया गया है, क्योंकि इस तिमाही में आपने एलपीएस योजना के लिए मंजूरी संख्या नहीं दी है?

परमिंदर चोपड़ा : पीएफसी ने संचयी रूप से लगभग 61,000 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं और लगभग 33,000 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि शेष राशि 22 से अधिकतम 48 महीनों की अवधि में होगी, इसलिए अगले दो से तीन वर्षों की अवधि में शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

श्रेय शिवानी : समझ गया मैडम। उपयोगी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोडरेटर : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न इक्विरस कैपिटल से श्रीपाल दोशी की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्रीपाल दोशी: मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद मैडम और अच्छे नंबरों के लिए बधाई। महोदया, पहला प्रश्न एनसीटीएल प्रस्तावों से संबंधित था। लैंको अमरकंटक के मामले में आपने कहा कि समाधान योजना में संशोधन किया गया है क्योंकि पहले अगर हम याद करें तो आरईसी और पीएफसी को एक तीसरी पार्टी बनानी थी और लैंको अमरकंटक फ्रेंचाइजी चलानी थी, तो अब समाधान योजना में क्या बदलाव है?

परमिंदर चोपड़ा : देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाधान योजना के तहत समाधान के लिए बेहतर प्रस्ताव आए हैं और आप जानते हैं कि ऋणदाता समाधान योजना के रूप में पीएफसी और आरईसी ने मूल्य अधिकतमकरण के लिए योजना प्रस्तुत की है क्योंकि हम सोच रहे थे कि वास्तविक वसूली योग्य मूल्य क्या है। प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमने इस अनुमान के आधार पर बोली लगाई है कि हम कुछ मूल्य अभिवृद्धि करेंगे और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे, इसलिए प्राप्त अस्थायी उद्धरणों के

आधार पर ऋणदाताओं ने नई बोली प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए एनसीएलटी से संपर्क किया है। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको सूचित किया है कि प्रक्रिया 6 फरवरी, 2024 को चलाई गई है और मूल्यांकन किया जा रहा है, इसलिए एक बार मूल्यांकन समाप्त हो जाने के बाद हम अनुमोदन के लिए एनसीएलटी को सफल समाधान योजना प्रस्तुत करेंगे।

श्रीपाल दोशी : ठीक है तो अब हम इस परियोजना के लिए नए बोलीदाताओं का इंतजार करेंगे?

परमिंदर चोपड़ा : हां, हम सफल समाधान योजना मूल्यांकन की प्रतीक्षा करेंगे और फिर हम जाएंगे।

श्रीपाल दोशी : क्या आपको यह और कोई अन्य लेखा मिला जो इस लैंको अमरकंटक के अलावा समाधान के अग्रिम चरण में है?

परमिंदर चोपड़ा : हम चालू वित्त वर्ष में एक अन्य परिसंपत्ति के समाधान पर भी विचार कर रहे हैं, वह जल विद्युत परिसंपत्ति है जो एनसीएलटी के बाहर है और हमें उम्मीद है कि समाधान योजना को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

श्रीपाल दोशी : मैडम क्या आपको का नाम साझा करने में कोई आपत्ति है जैसे कि हमारे पास एक्सपोज़र की मात्रा क्या है?

परमिंदर चोपड़ा : यह डैन्स के समान है। यह शिगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिस पर पीएफसी का लगभग 500 करोड़ रुपये बकाया है।

श्रीपाल दोशी : ठीक है, समझ गया और महोदया, अंतिम प्रश्न विकास पक्ष से संबंधित था, जैसा कि पहले प्रतिभागी भी संकेत कर रहा था, इसलिए हम वित्त वर्ष 2024 के लिए 13% से 14% के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं या जैसे कि वहाँ कोई डिस्कनेक्ट है?

परमिंदर चोपड़ा : देखिए, अभी तक मैं जो कह सकती हूं वह यह है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह केवल इसी सीमा के बीच रहने वाला है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले वर्ष के लिए यह 12% से 15% के आसपास हो सकता है।

श्रीपाल दोशी : ठीक है और वित्त वर्ष 2025 के लिए चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया गया है, इसलिए हमें बेहतर गति देखनी चाहिए, तो क्या वित्त वर्ष 2025 में विकास की गति बेहतर होगी?

परमिंदर चोपड़ा : हां, हम अगले वित्तीय वर्ष में भी इसके इसी दायरे में रहने की उम्मीद कर रहे हैं।

श्रीपाल दोशी : ठीक है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोडरेटर : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न बी एंड के सिक्यूरिटीज से जिगर के जानी की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

जिगर के जानी: मेरा प्रश्न लेने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि हमने इस वर्ष के लिए नौ महीने विव2024 तक क्या प्रतिबंध लगाए हैं?

परमिंदर चोपड़ा: अब तक 1,44,000 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई है।

जिगर के जानी : समझ गया और क्या यह साझा करना संभव होगा कि लैंको पर हमारा प्रावधान कवर क्या होगा जो हम बहीखातों पर ले जा रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा : हो सकता है ये 50% के आसपास हो।

जिगर के जानी : 50% ठीक है और महोदया, विकास फ्रंट पर फिर से विकास वापस आ रहा है, हमने आरईसी को देखा है कि हमारी सहायक कंपनी बहुत तेज गति से बढ़ रही है और वे भी

उसी तरह के रनवे पर पूंजी लगा रहे हैं जो हमारे पास आरईसी साइड इन्फ्रा के साथ-साथ सरकारी परियोजनाओं पर भी है। विशेष कारण यह है कि हमारे और आरईसी के विकास के बीच इतना तीव्र अंतर क्यों है और दूसरा, अगर मुझे पिछली तिमाही को देखना है तो आपने कहा था कि मध्यम से दीर्घकालिक विकास लगभग 15% से 20% होगा, तो क्या अब थोड़ा सा होगा निचले स्तर पर थोड़ा सा गिरावट, हम एक वर्ष के लिए मध्यम से दीर्घावधि में कुल मिलाकर लगभग 15% की वृद्धि देख रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा: विकास फ्रंट पर देखें, मैं इसकी तुलना आरईसी से नहीं करना चाहती क्योंकि हर कंपनी की अपनी नीति होती है, लेकिन हम लंबी अवधि में स्थायी विकास चाहते हैं, यही मैं कह सकती हूं और यदि आप देखें तो हम ऐसा कर चुके हैं, के बारे में बात कर रहे हैं और पिछली कॉल में आपने सही पक्ष कहा था कि मैंने 15% से 20% की वृद्धि की बात कही थी, इसलिए तीसरी तिमाही तक हमारे पास पहले से ही लगभग 16% की वृद्धि है और आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं 12% से 15% की वृद्धि क्यों कह ररी हूं, लेकिन वह कम है ति4 अन्यथा पिछले वर्षों में भी हमारा संवितरण पहले की तीन तिमाहियों की तुलना में अधिक है, इसलिए इस वर्ष रणनीति के रूप में हमने ध्यान रखा है और यदि आपने देखा होगा कि ति1 में भी हमारे पास बहुत अच्छे विकास आंकड़े हैं। पिछले वर्षों की तुलना में, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा संवितरण भी पूरे वर्ष और प्रत्येक तिमाही में समान रूप से फैले, इसलिए यह हमारी रणनीति में बदलाव है जो हमने चालू वित्तीय वर्ष में किया है और इसीलिए मैं ऐसा कह ररी हूं। हमारी वृद्धि इन आंकड़ों के भीतर बनी रहेगी और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि यह लंबे समय तक टिकाऊ आधार पर बनी रहेगी।

जिगर के जानी: समझ में आया मैडम और अंत में हम अपने एनआईएम को बनाए रखेंगे और मार्गदर्शन को लगभग 3.5% एनआईएम और 2.5% स्प्रेड पर फैलाएंगे, जिसे हम देख रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा: हाँ, हम इसे बनाए रखने की आशा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन उन संख्याओं के लिए है।

जिगर के जानी: निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए वापस आऊंगा। धन्यवाद।

मोडरेटर: धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एमएलपी से निशांत शाह की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

निशांत शाह : तिमाही के लिए बधाई और आंशिक रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, प्रश्न विकास की तरह है? क्या हम अभी कुछ हद तक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं? आपने अगले वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की नई फंडिंग जुटाने के बारे में बताया? हमें इसे कैसे देखना चाहिए? क्या ऐसा लगता है कि आप अगले साल बेहतर विकास की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चालू हो रही हैं और आप उसके लिए अपनी क्षमता को संरक्षित कर रहे हैं या हमें अगले साल के लिए विकास के बारे में कैसे सोचना चाहिए? इस वर्ष इसे संभवतः कुछ आधार प्रभाव के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन अगले वर्ष के लिए हमें विकास के बारे में कैसे सोचना चाहिए?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले साल भी हम इसी तरह के आंकड़े देख रहे हैं। विकास अंततः नवीकरणीय पर आने वाला है। ऊर्जा परिवर्तन और उपकरण निर्माण पर नवीकरणीय क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है, भारत में

उपकरण निर्माण के लिए बहुत गुंजाइश है और दूसरी ओर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आरडीएसएस संवितरण और आरडीएसएस संस्वीकृति में तेजी आने वाली है। अगले वित्तीय वर्ष से ये दो फ्रंट हैं। एक और कारक है यदि आपने माननीय विद्युत मंत्री का बयान सुना है कि देश की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, तो इससे हमारा मतलब है कि हम कुछ नई थर्मल पावर परियोजनाएं जोड़ेंगे या जहां भी थर्मल पावर परियोजनाएं रुकी हुई थीं, काम फिर से शुरू किया जाएगा जिससे फंडिंग का मौका मिलेगा क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हम ऐसी सभी परियोजनाओं में प्रमुख ऋणदाता रहे हैं। हाइड्रो फिर सरकार का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर खासा फोकस है। हर कोई अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व में आने वाली विशाल क्षमताओं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन गतिविधियों में भी हमारी अच्छी हिस्सेदारी होगी। जहां कहीं भी धन की दीर्घकालिक आवश्यकता होती है, वह भी लंबी अवधि की होती है और मात्रा अधिक होती है, मुझे लगता है कि हम उन सभी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। यह ऊर्जा पक्ष पर है और अब अगर हम धीरे-धीरे बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रतिबंध हमने पहले ही कर दिए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे अगले वित्तीय वर्ष में संवितरण में बदल जाएंगे। इसके अलावा पाइपलाइन के कई प्रस्ताव हैं, चाहे वह महानगरों की फंडिंग हो, हम बंदरगाहों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। हमने पहले भी यह डेटा साझा किया है कि हम अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण कर रहे हैं। ढेर सारा ऊर्जा परिवर्तन, ई वाहन और सभी फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इन सभी क्षेत्रों में अपना हिस्सा हासिल कर लेंगे।

निशांत शाह: आप का धन्यवाद मैडम। वहाँ कुछ अनुवर्ती प्रश्न हैं? सबसे पहले आपने थर्मल और हाइड्रो और अन्य पारंपरिक जैसे गैर-नवीकरणीय पारंपरिक प्रकार जैसे बिजली वित्तपोषण के लिए कुछ क्षमता को संरक्षित करने का उल्लेख किया? क्या आप यह

बताने में सक्षम होंगे कि यह कितना होना चाहिए और उस प्रश्न का दूसरा भाग नवीकरणीय है जिसे हम समझते हैं कि कम मार्जिन या कम प्रकार का यिल्ड वाला व्यवसाय है? क्या हमें इसे इस तरह देखना चाहिए कि यदि आप अधिक तापीय परियोजनाएँ करते हैं तो क्या यह उच्च ऋण प्रसार पर आएगा क्योंकि वहाँ अतिरिक्त जोखिम है और इसलिए हमें उस संदर्भ में मार्जिन के बारे में कैसे सोचना चाहिए और दूसरी बात यह है कि यह एक गुणात्मक प्रश्न है जैसे कि पीएफसी और आरईसी दोनों अब बिजली क्षेत्र के फाइनेंसरों से हटकर अधिक व्यापक बुनियादी ढांचे के फाइनेंसरों में विविधता ला रहे हैं, तो क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि मानव पूंजी के संदर्भ में आपने किस प्रकार की क्षमता में वृद्धि की है, इन मूल्यांकनों के लिए बाहर से लोगों को काम पर रखना है। गैर विद्युत संबंधी परियोजनाएँ? बिजली हमारी ताकत रही है लेकिन अन्य परियोजनाओं के बारे में क्या आप इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, इसलिए ये दो तरह के अनुवर्ती प्रश्न हैं?

परमिंदर चोपड़ा : ठीक है, आपने जोड़ी जाने वाली क्षमताओं के बारे में बात की, तो 31 दिसंबर, 2023 तक कुल स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, जिसके अगले पांच से छह वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है। हमें लगभग 800 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है और माननीय प्रधान मंत्री के बयान के अनुसार इसमें से लगभग 50% नवीकरणीय क्षमता होगी। अगर हम राष्ट्रीय बिजली योजना को देखें तो इसके लिए लगभग 33 लाख करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश की आवश्यकता है, अगर हम 500 गीगावाट क्षमता वृद्धि और बैटरी भंडारण और गैर जीवाश्म ईंधन के आधार पर पूंजी निवेश की बात करें तो हम 19% की उम्मीद कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन में निवेश, इसलिए यदि हम इन संख्याओं को देखें और यदि आप हमारी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी को देखें, तो हम स्टैंडअलोन आधार पर बिजली क्षेत्र के लिए कुल ऋण का 20% से 25% तक वित्त पोषण कर रहे हैं, इसलिए इन आंकड़ों के अनुसार, आप इसे बहुत अच्छी तरह से

कार्यान्वित कर सकते हैं। यह ऊर्जा ट्रांसिशन की बात नहीं करता। यह मूल रूप से केवल क्षमता वृद्धि के लिए वित्त पोषण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि उपकरण निर्माण, ऊर्जा संक्रमण तो बिजली क्षेत्र में धन की आवश्यकता कहीं अधिक होगी। इसके अलावा वितरण क्षेत्र और तदनुसार ट्रांसमिशन क्षेत्र को भी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों के संबंध में, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी साझा किया है कि शुरुआत में हम बैंकों द्वारा वित्त पोषित की जा रही परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं और उसमें से एक हिस्सा ले रहे हैं। हम जानते हैं कि अब तक हमारे पास केवल बिजली क्षेत्र में क्षमताएं हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों जैसे सड़क, रिफाइनरी, मेट्रो और बंदरगाह आदि में अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम अपने मौजूदा कार्मिकों की क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही हम खुद को मजबूत करने के लिए क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों की भी तलाश कर रहे हैं।

निशांत शाह: समझा। क्या आप पारंपरिक परियोजनाओं पर मार्जिन के बारे में बात कर सकते हैं जैसा कि मैं व्याख्या कर रहा हूं कि यदि हम अधिक पारंपरिक वित्तपोषण करते हैं तो क्या इससे आगे चलकर हमारे मार्जिन में सुधार होगा?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए, आपने सही कहा कि नवीकरणीय क्षेत्र में मार्जिन पर हमेशा दबाव रहता है क्योंकि हम कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं और फिर भी हम नवीकरणीय क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वित्तपोषक में से एक हैं और इसकी भरपाई मौजूदा पीढ़ी के ट्रांसमिशन और से की जा रही है। वितरण क्षेत्र का पोर्टफोलियो और आगे भी, मैं इस बात से सहमत हूं कि पारंपरिक पीढ़ी थोड़ा अधिक मार्जिन देती है, लेकिन अब कंपनियों के पास फंडिंग के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धी दबाव हमेशा हम पर रहता है, इसलिए हम हमेशा यह मार्गदर्शन देते रहे हैं कि हम करेंगे। हम अपने स्प्रेड को 2.5% के आसपास बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे।

निशांत शाह: मेरी ओर से इतना ही । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोडरेटर: धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न बोहेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से सोनल की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

सोनल : इस अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, मेरा प्रश्न विकास से संबंधित था और मुझे एक पृष्ठभूमि बताइए कि हर कोई इसे स्पष्ट करने का प्रयास क्यों कर रहा है? चूँकि दीर्घकालिक मार्गदर्शन 15% से 20% है और हम इस वर्ष 13% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं और अगले वर्ष लगभग 13% की समान वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम रूढ़िवादी हो रहे हैं और यह एक सामान्य संख्या है जो हम दे रहे हैं एक रूढ़िवादी प्रबंधन होने के नाते या ऐसा है कि विकास काफी हद तक पीछे की ओर जा रहा है और इसलिए जबकि इस वर्ष और अगले वर्ष विकास केवल 13% है, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से संचयी विकास दर 15% से 20% है और इसलिए भविष्य के लिए 2025 के बाद के वर्षों में विकास दर काफी अधिक होगी? धन्यवाद?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए, केवल एक संख्या बताने के लिए हम कोई भी संख्या बता सकते हैं, यह एक अलग बात है लेकिन हम थोड़ा यथार्थवादी होना चाहते हैं। मैंने चालू वित्त वर्ष के लिए 13% का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। मैंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए यह लगभग 15% होने जा रहा है और साथ ही हम अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी इतनी ही संख्या की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि बढ़ते आधार पर यदि 15% पहले ही बढ़ चुका है इस वर्ष और बढ़ते आधार पर हम आपको 15% वृद्धि का आश्वासन दे रहे हैं ताकि पुनर्भुगतान भी हो सके, इसलिए औसतन हमारे पास संपत्ति के औसत जीवन की छह साल की परिसंपत्ति पुस्तक है, इसलिए औसतन आप यह पता लगा सकते हैं कि यदि हम 4,60,000 करोड़ रुपये का

वित्त पोषण हमारी उत्कृष्ट बुक है। औसत पुनर्भुगतान क्या होगा और विस्तारित आधार पर हमें कितना वितरित करना है, आप बहुत अच्छी तरह से संख्याओं का पता लगा सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम लगभग 15% का यथार्थवादी लक्ष्य देना चाहेंगे।

सोनल: उस पर बस एक जवाबी सवाल? चूँकि आपने बताया कि दीर्घावधि 15% से 20% है और आपका आधार दीर्घावधि में बढ़ता रहेगा, इसलिए आपने 15% से 20% के बीच की बात की, क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि दीर्घावधि में 15% से 20% की वृद्धि के उच्च आधार के बावजूद टर्म, क्योंकि थर्मल की क्षमता में वृद्धि, जिसके कारण वृद्धि होती है, हमारे पास देरी से आएगी क्योंकि यह परियोजनाओं को शुरू करने और फिर पूंजीगत व्यय के रूप में वितरित करने की एक लंबी प्रक्रिया है?

परमिंदर चोपड़ा: मुझे लगता है कि आपकी चिंता सही है कि हम अभी जो भी क्षमताएं हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यह कोई बहुत लंबा लक्ष्य नहीं है। हम अगले तीन से पांच साल के बारे में ही सोच रहे हैं।' अभी हमारे पास जो भी प्रतिबंध हैं वह अगले दो से तीन वर्षों में परिपक्व हो जाएंगे और हम जो भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक नई जलविद्युत परियोजना के लिए समय लगेगा लेकिन कुछ तापीय क्षमताएं हैं जिनके लिए केवल विस्तार करना होगा इसलिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की तरह इसमें समय नहीं लगेगा इसलिए विस्तार की गुंजाइश है मौजूदा परियोजनाओं में। वहां हम नई क्षमताएं जोड़ने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए इसमें लंबे समय तक समय नहीं लगेगा और मुझे लगता है कि यह जल्द ही आ सकता है, विद्युत मंत्रालय उम्मीद कर रहा है कि यह आवश्यक क्षमता अगले दो से तीन वर्षों में जोड़ी जाएगी इसलिए उसके आधार पर हम सोचते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन और नए रास्ते तलाशने के पर्याप्त अवसर हैं। सब जानते हैं। आपने बजट में देखा है कि ऑफशोर

विंड के लिए वीजीएफ दिया गया है, कोई नया क्षेत्र आ रहा है। हाइड्रोजन के मोर्चे पर प्रगति हुई है, इसलिए इन सबको मिलाकर हम सोचते हैं कि यह एक टिकाऊ स्तर है।

सोनल: स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया।

मोडरेटर: धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न आनंद राठी के कैटव की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

कैटव: बधाई हो मैडम। मेरे दो प्रश्न थे। नंबर एक यह था कि क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि अभी प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता क्या है, यह देखते हुए कि सेक्टर मैक्रो में सुधार हुआ है तो क्या बैंक अब इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से क्या देख रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए, आप जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के तहत हम पहले से ही बैंकों और अन्य एफआई से प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थर्मल या हाइड्रो के लिए देखें तो आप जानते हैं कि परियोजना की लागत बहुत बड़ी है, इसलिए यह किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ऋणदाता इसे स्टैंडअलोन आधार पर वित्तपोषित करें, इसलिए कंसोर्टियम होना चाहिए और जिस प्रकार के एक्सपोज़र हम ले सकते हैं, कोई भी अन्य फाइनेंसर लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए एक समूह के रूप में हम थर्मल प्रोजेक्ट के वित्तपोषण में ऊपरी हाथ रखते हैं या ऐसा हो जलविद्युत परियोजना में छोटे हिस्से हो सकते हैं जिन्हें बैंकों द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन उनकी क्षेत्रीय सीमाएँ हैं, उनकी एक्सपोज़र सीमाएँ हैं, व्यक्तिगत कंपनी एक्सपोज़र सीमा है, इसलिए मुझे लगता है कि हम ऐसी सभी परियोजनाओं में अधिक एक्सपोज़र लेने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

कैटव: समझ गया। महोदया, दूसरी बात यह है कि इस तिमाही के दौरान धन की लागत के संदर्भ में, यह देखते हुए कि कई बैंक तंग तरलता की स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं और क्या इससे कम से कम निकट अवधि में कोई मार्गदर्शन बदल जाएगा? मैं जानता हूं कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण हम अभी भी वैसा ही बनाए हुए हैं, लेकिन अल्पावधि में क्या इसमें किसी भी तरह से बदलाव होता है?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए आपने सही कहा है कि बाजार में तरलता की कमी है और ब्याज दरें सख्त हो रही हैं, हालांकि आरबीआई दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो चालू वित्त वर्ष में हमारे फंड की बढ़ी हुई लागत के आधार पर हम हमने अपनी ऋण ब्याज दर की समीक्षा की है और हमने धन की लागत में वृद्धि के अनुरूप उनमें वृद्धि की है। यही कारण है कि अंततः आप देख रहे हैं कि हम अवधि के दौरान प्रसार को बनाए रखने में सक्षम हैं और हम इसे बनाए रखने की उम्मीद करते हैं क्योंकि हम तिमाही आधार पर अपनी ब्याज दरों की समीक्षा कर रहे हैं।

कैटव: समझ गया ठीक है। आप का धन्यवाद मैडम। यह बहुत मददगार है।

मोडरेटर : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एक्विटास इन्वेस्टमेंट से निहारिका की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

निहारिका : अवसर के लिए शुक्रिया। तो मेरा पहला प्रश्न अंतिम प्रतिभागी का अनुवर्ती है? आपने कहा कि हमारी ऋण दरें अब हमारे लिए धन की लागत में वृद्धि के अनुरूप बढ़ रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी रीसेट अवधि थोड़ी लंबी है, तो क्या आप इस तथ्य के बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि वास्तव में इसे पारित होने में कितना समय लगेगा। दरों पर और क्या हम मार्जिन में कुछ संकुचन देखेंगे?

परमिंदर चोपड़ा: हमारी रीसेट अवधि देखें, कुछ मामलों में यह एक वर्ष है, यह तीन वर्ष या पांच वर्ष है, इसलिए हमारे पास ऋणकर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर अलग-अलग रीसेट तिथि है, भले ही यह एक वर्ष हो, कार्ड दर जो भी हो आज की तारीख में यह रीसेट पर लागू होगा इसलिए यदि हमारी ऋण लेने की लागत बढ़ रही है तो स्वचालित रूप से सभी रीसेट संशोधित दरों पर होंगे। इसलिए नए संवितरण के अलावा जो संशोधित दरों पर किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे मंथन या प्रसार प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

निहारिका: ठीक है, यह मददगार था और मेरा दूसरा प्रश्न डैन्स एनर्जी पर है, तो क्या हमने प्रावधानों पर कोई वापसी की है या मूल रूप से कितना प्रावधान था और उस पर कितनी वसूली हुई थी?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए चालू तिमाही के दौरान लगभग 79 करोड़ रुपये का प्रावधान रिवर्सल है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि 90% रिकवरी रेट था।

निहारिका: मेरा दूसरा प्रश्न लैंको पर है, इसलिए मैं बस इस पर प्रबंधन के दृष्टिकोण को समझना चाहती हूं, इसलिए यदि हमें इसके लिए बेहतर बोली मिल रही है तो क्या हम अभी भी अपनी ओर से बोली लगा रहे हैं और फिर भी हम इसे अपनी बुक में फिर से लेने के लिए ठीक हैं? क्या हम मूल रूप से एक ऋणदाता के रूप में नहीं बल्कि अपनी बुक में लैंको अमरकंटक के अधिग्रहण के रूप में एक और बोली प्रस्तुत कर रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा: मुझे लगता है कि जब तक मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता, मैं यह जानकारी साझा नहीं करना चाहूंगी और मुझे लगता है कि इससे पहले मैं खुद को सही करना चाहूंगी। पहले हमने कहा था कि हम लैंको के मामले में 50% का प्रावधान बनाए रख रहे हैं, लेकिन

वास्तव में यह 76% है, हम लैंको अमरकंटक के मामले में प्रावधान बनाए रख रहे हैं और हम एनसीएलटी द्वारा इस नई योजना को स्वीकार किए जाने की स्थिति में उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं।

निहारिका: ठीक है और मुझे यकीन नहीं है कि इसका उत्तर दिया गया था या नहीं? 31 दिसंबर, 2023 तक हमारी संस्वीकृति बुक क्या है?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए चालू वर्ष की संस्वीकृति लगभग 1,44,000 करोड़ रुपये है और मुझे लगता है कि पिछले वर्ष से हम इसे जारी रख रहे हैं, हो सकता है कि मेरे पास अभी यह आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।

निहारिका: ठीक है और मूल रूप से ब्याज के मामले में हम मूल रूप से धन की लागत का प्रबंधन कैसे करने की योजना बना रहे हैं? मूलतः क्या हम अधिक विदेशी ऋण लेने की योजना बना रहे हैं क्योंकि विशेष रूप से भारत में ब्याज लागत बढ़ रही है?

परमिंदर चोपड़ा: देखें कि क्या भारत में ब्याज दरें सख्त हो रही हैं और मुझे लगता है कि अगर हम इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से उधार लेते हैं तो भी ऐसी ही स्थिति होती है, इसलिए अगर हम आज की तारीख में देखें तो हमारे पास विदेशी मुद्रा में 18% ऋण है। 19% बैंकों से आरटीएल है एफआई और घरेलू बॉण्ड 58% का गठन करते हैं इसलिए ये स्रोत प्रमुख हैं लेकिन हम हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए मिश्रण को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं कि हमारी ऋण लेने की कुल लागत सीमा के भीतर बनी रहे, इसलिए यह सब बाजार पर निर्भर करता है कि क्या बॉण्ड बाजार हमें वह अवसर देता है और जैसा कि पहले कहा गया था, हमने हमेशा कहा है कि हम अपने ऋण का लगभग 20% विदेशी मुद्रा बाजार में बनाए रखना चाहते हैं। पिछले साल हमने जेपीवाई में धन जुटाया है।

इस वर्ष हमने डॉलर में सिंडिकेटेड ऋणों के माध्यम से भी धन जुटाया है, इसलिए इन नौ महीनों में यह लगभग 12.42% है जो विदेशी मुद्रा में किया गया है। बॉण्ड का गठन लगभग 44% है। आप जानते हैं कि हमने सार्वजनिक निर्गम भी लॉन्च किया है जिससे हमें 2824 करोड़ रुपये मिले हैं। इस वर्ष आरटीएल में भी हमने काफी धन जुटाया है और यह कुल ऋण का लगभग 25% है।

निहारिका: ठीक है यह मददगार था। मेरी तरफ से यही था। धन्यवाद।

मोडरेटर: धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न मैक्सिमल कैपिटल से सर्वेश गुप्ता की पंक्ति से है। कृपया अपना प्राशन पूछें।

सर्वेश गुप्ता: शुभ संध्या महोदया। मेरे अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। ति4 के लिए अपेक्षित संवितरण क्या है और अगले वर्ष के लिए आप किस प्रकार की संवितरण वृद्धि दर का अनुमान लगा रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए, हमने कहा है कि हम 15% की ऋण वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम होंगे, इसलिए हम इसे बनाए रखने में सक्षम होंगे। मैं तो यही कह सकती हूं।

सर्वेश गुप्ता: समझ गया महोदया और दूसरी बात बुनियादी ढांचे के मामले में आपने कहा था कि अभी तक संवितरण केवल 2000 करोड़ रुपये है, तो इस विशेष खंड में अगले वर्ष के लिए क्या योजनाएं हैं?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस साल हमने अब तक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगभग 33,000 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं, इसलिए हम कुछ संवितरणों को लेने के लिए छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ संवितरण हम इस चालू तिमाही में

कर पाएंगे, लेकिन उनमें से अधिकांश जा रहे हैं अगले वित्तीय वर्ष में जाना है इसलिए इसे संवितरण में परिवर्तित होने में समय लगेगा।

सर्वेश गुप्ता: समझ गया और अंत में आपने कहा कि इस वर्ष आपने जो संस्वीकृति दी है वह 1.44 लाख करोड़ रुपये है और पिछले साल संचयी संस्वीकृति जो संवितरित नहीं की गई थी वह 1.5 लाख करोड़ रुपये थी, तो क्या कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 3 लाख करोड़ रुपये हैं जो कि संस्वीकृत नहीं हैं अभी तक वितरित नहीं किया गया है या अब तक मूल्य क्या होगा?

परमिंदर चोपड़ा: देखिए मेरे पास नंबर नहीं हैं. मैंने बताया था कि मैंने सिर्फ अपना अनुमान लगाया था। अभी मेरे पास उन प्रतिबंधों की संख्या नहीं है जो पिछले वर्ष के लिए अभी तक संवितरित नहीं किए गए हैं।

सर्वेश गुप्ता: नहीं, क्या अभी तक आपके पास संचयी संस्वीकृतियाँ हैं जो अभी तक वितरित नहीं की गई हैं?

परमिंदर चोपड़ा: नहीं, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वह संख्या नहीं है, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.44 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन पिछले वर्ष के लिए यह सिर्फ मेरा अनुमान है कि यह लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये है।

सर्वेश गुप्ता: समझ गया मैडम। ठीक है धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा: नंबर इसलिए भी सही नहीं होगा क्योंकि मेरे पास नहीं है।

सर्वेश गुप्ता: ज़रूर मैडम। धन्यवाद।

मोडरेटर : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एलारा कैपिटल से हिमांशु ध्यावाला की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें ।

हिमांशु ध्यावाला: तो मूल रूप से मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि नवीकरणीय पोर्टफोलियो के बारे में आगे कैसे बढ़ना है, जो कर्षण हम देख रहे हैं और भविष्य में हम विव2025 या विव 2026 के बारे में अच्छे अवसर देख रहे हैं?

परमिंदर चोपड़ा: मुझे लगता है कि अगर हम आज की तारीख में समग्र आधार पर देखें तो हमारा नवीकरणीय पोर्टफोलियो लगभग 12% है, इसलिए हम इसकी तलाश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले दो से तीन वर्षों में यह कुल पोर्टफोलियो का लगभग 20% हो सकता है।

हिमांशु ध्यावाला: ठीक है बढ़िया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोडरेटर: धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड से नीलेश जेठानी की पंक्ति से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

नीलेश जेठानी: शुभ संध्या और अवसर के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल उस एमओयू पर था जिस पर हमने पिछले साल जुलाई में गोवा में लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये के लिए हस्ताक्षर किए थे, उसकी स्थिति क्या है? हम उस चरण में कहां हैं?

परमिंदर चोपड़ा: तो यह उपकरण निर्माण का एक संयोजन था, कुछ ऋणकर्ता हाइड्रोजन के लिए ऋण लेने का इरादा रखते थे। वे कुछ सरल सादे पवन नवीकरणीय परियोजनाएं थीं, इसलिए यदि आप देखें तो पवन और संवितरण के लिए हमारी मंजूरी दिन-ब-दिन बढ़ रही है और इसलिए उस समय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपकरण निर्माण की अगर हम बात करें तो हमने अडानी के लिए भी परियोजना को मंजूरी दे दी है, बाजार में सभी बड़े खिलाड़ियों के लिए हमने उपकरण निर्माण सुविधा को मंजूरी दे दी है जो

मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन सभी एमओयू और सभी उन एमओयू को हम तब संस्वीकृति दे रहे हैं जब ऋणकर्ता डीपीआर के साथ तैयार है।

नीलेश जेठानी: तो क्या आप 2.4 में से कोई संख्या बता सकते हैं जिसे आज तक संस्वीकृत किया गया है?

परमिंदर चोपड़ा: अभी मेरे पास वो नंबर नहीं हैं। हम आपके साथ अलग से साझा करेंगे।

नीलेश जेठानी: ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न बुनियादी ढांचे के बारे में था, इसलिए आज निश्चित रूप से हमने 33,000 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की है, लेकिन इस पहलू पर मैं यह समझना चाहता था कि कुछ समय पहले तक आप संस्वीकृत आदि के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त करके हमारी क्षमता में सुधार या वृद्धि कर रहे थे। परियोजनाओं और क्षेत्र की गहरी समझ के लिए तो आज हम कहां हैं? क्या आपको लगता है कि क्या हमने यह कमी पूरी कर दी है? वित्त वर्ष 2027 से आगे बढ़ते हुए क्या हम एक अच्छी विकास दर की उम्मीद कर सकते हैं जहां तक बुनियादी ढांचा ऋण देने या संस्वीकृति देने का सवाल है तो पीएफसी स्तर पर जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है?

परमिंदर चोपड़ा: पीएफसी में देखें, हम बुनियादी ढांचे क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अपने कार्मिकों को उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेज रहे हैं। यदि हम बायोमास जैसे कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो हम रिफाइनरियों के बारे में बात कर सकते हैं, और हम इथेनॉल परियोजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे कार्मिकों ने कई परियोजनाओं से अवगत कराया है और इसका मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित की है। सड़कों पर हमने कई परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है,

इसलिए हम कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और जहां भी आवश्यक हो, हम अब तक बाहरी विशेषज्ञों की मदद लेते हैं और हम आगे भी उन विशेषज्ञों को अपने रोल में रखने की योजना बना रहे हैं।

नीलेश जेठानी: समझ गई और मेरी ओर से मेरा आखिरी सवाल यह है कि मैं सिर्फ प्रतिस्पर्धी तीव्रता को समझना चाहता था? निश्चित रूप से आप पिछले प्रतिभागियों के प्रश्न में इसके आधार पर हैं, लेकिन चूंकि पांच साल पहले और बहुत से पीएसयू बैंक आज की तुलना में अपनी क्षमता का बहुत अधिक मूल्य के लिए संतुलन बना रहे थे, तो क्या आप मुझे पांच साल पहले के 100 रुपये को समझने में मदद कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को दिया गया ऋण पीएफसी और आरईसी या पावर फाइनेंसर्स की बाजार हिस्सेदारी क्या थी, पांच साल बाद आज क्या है और आगे इस बारे में आपका क्या आकलन है?

परमिंदर चोपड़ा: पहले भी देखें, मुझे लगता है कि मूल्यांकन तब किया गया था जब हमने आरईसी का अधिग्रहण किया था, आरईसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी थी। उस समय यह आकलन किया गया था कि लगभग 20% से 25% बाजार हिस्सेदारी पीएफसी की है और इतनी ही हिस्सेदारी आरईसी की भी है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो हमने अधिग्रहण के समय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संस्वीकृति ली थी और अगर आप आज भी बात करें तो आज हमने आकलन नहीं किया है लेकिन हो सकता है कि हम अभी भी उसी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रख रहे हों।

नीलेश जेठानी: बाजार हिस्सेदारी समान रहने की उम्मीद है, इसलिए अगले सात से आठ वर्षों के लिए प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की उम्मीद के साथ समझना चाहते हैं? हम भविष्य में कम विकास दर की उम्मीद क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं देखूं तो अतीत में सौर क्षमताएं प्रति वर्ष 40 गीगावाट से 50 गीगावाट की सीमा में थीं, लेकिन अब आप नवीकरणीय क्षेत्र में कम से कम 50 गीगावाट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें

क्या रुकावट है? हमें वह उच्च मार्गदर्शन देने से या आप किसी और चीज़ का आकलन कर रहे हैं जिसे हम समझने में असमर्थ हैं?

परमिंदर चोपड़ा: मैं किसी और चीज का आकलन नहीं कर रही हूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब भी कुछ होगा और वह मेरे हाथ में होगा, तभी मैं कोई मार्गदर्शन साझा कर पाऊंगी, इसलिए कोई भी नंबर देना निवेशकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी।' वास्तव में मैं ऐसी कोई संख्या नहीं देना चाहती।

नीलेश जेठानी: ठीक है, लेकिन आम तौर पर आप उम्मीद करते हैं कि बाजार हिस्सेदारी समान रहेगी?

परमिंदर चोपड़ा: हाँ। वह वहां है और मैंने इस क्षेत्र में अपेक्षित पूंजीगत व्यय के साथ-साथ जो संख्याएं साझा की हैं, उन्हें भी साझा किया है, इसलिए इस समय मैं यही कह सकती हूं।

नीलेश जेठानी: कोई बात नहीं मैडम। यह मददगार था और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोडरेटर : धन्यवाद। समय के अभाव के कारण यह आज का आखिरी प्रश्न था और अब मैं सम्मेलन को समापन टिप्पणियों के लिए सुश्री श्वेता दफ़्तरदार को सौंपता हूँ। मैडम आप कहिए।

श्वेता दफ़तरदार : धन्यवाद मानव। एलारा सिक्योरिटीज लिमिटेड की ओर से, हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंधन को इस अर्निंग कॉल की मेजबानी करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद टीम। आप सभी को धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

मोडरेटर: धन्यवाद। एलारा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सम्मेलन का समापन हुआ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अब आप अपनी लाइनें काट सकते हैं।

***